नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 119
दि. 01.02.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

रिकॉर्ड नौवां बजट, अर्थव्यवस्था से लेकर आम आदमी तक पर पड़ेगी सीधी छाप

नई दिल्ली। आज देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला यूनियन बजट 2026 संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह उनका लगातार नौवां पूर्णकालिक बजट होगा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही यह मोदी सरकार का 15वां बजट भी है। एक और खास बात यह है कि पहली बार देश का आम बजट रविवार को पेश किया जा रहा है, जिस पर सुबह से ही देशभर की नजरें टिकी हुई हैं। निवेशक, उद्योग जगत, किसान, मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिक—हर किसी को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। इस बार का बजट केवल कर राहत या खर्च बढ़ाने तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे आर्थिक स्थिरता, दीर्घकालिक विकास और वित्तीय अनुशासन के संतुलन के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का फोकस ऋण-जीडीपी अनुपात को नियंत्रित करने पर रहेगा, जो फिलहाल लगभग 56 प्रतिशत के आसपास है। वित्त मंत्रालय के संकेत बताते हैं कि इस बार सरकार किसी सख्त राजकोषीय घाटे के लक्ष्य की जगह ज्यादा पारदर्शी और लचीले वित्तीय मानकों को अपनाने की दिशा में कदम उठा सकती है, ताकि विकास की रफ्तार भी बनी रहे और आर्थिक सेहत भी मजबूत हो। करदाताओं के लिए यह बजट बेहद अहम माना जा रहा है। लंबे समय से नए टैक्स रेजीम में राहत बढ़ाने की मांग उठ रही है। मौजूदा व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन इसे बढ़ाकर 14 लाख रुपये करने की मांग जोर पकड़ रही है। अगर ऐसा होता है, तो मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों की जेब में सीधा पैसा बचेगा। वहीं पुराने टैक्स रेजीम को लेकर भी उम्मीदें हैं कि बेसिक छूट सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया जा सकता है, जिससे उन करदाताओं को राहत मिलेगी जो अभी भी पुरानी व्यवस्था को पसंद करते हैं। टीडीएस को लेकर भी बजट में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। खासतौर पर सीनियर सिटीजन और किराये की आय पर टीडीएस सीमा बढ़ाने की मांग है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस छूट को मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक किए जाने की उम्मीद की जा रही है, जिससे उन्हें बार-बार रिफंड के झंझट से राहत मिल सके। इसी तरह किराये की आय पर टीडीएस सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक करने की चर्चा है। रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में भी बड़ा बदलाव संभव माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार रिटायरमेंट के समय एनपीएस फंड की 80 प्रतिशत निकासी को टैक्स फ्री कर सकती है। इससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और स्वैच्छिक एनपीएस निवेशकों को लंबी अवधि के लिए बचत के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। जीएसटी सुधार भी इस बजट का अहम हिस्सा हो सकता है। शिक्षा, एमएसएमई और रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के लिए कुछ दरों में संशोधन की उम्मीद है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। अगर ऐसा होता है, तो ईंधन की कीमतों में स्थिरता आ सकती है, हालांकि राज्यों के राजस्व पर इसके असर को लेकर सरकार को संतुलन साधना होगा। इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर भी सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। खासतौर पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए नए फ्रेमवर्क की घोषणा संभव है। इससे न सिर्फ आम लोगों को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सोना और चांदी पर टैक्स राहत की मांग ज्वेलरी इंडस्ट्री लंबे समय से कर रही है। बजट 2026 में इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी दरों में कटौती की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही ज्वेलर्स को टैक्स भुगतान के समय में राहत देने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं, जिससे इस सेक्टर में कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। किसानों के लिए भी यह बजट बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को मौजूदा 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की मांग लगातार उठ रही है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ाने जैसे कदमों की उम्मीद की जा रही है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। शेयर बाजार और निवेशकों के लिए भी बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में राहत मिलने पर बाजार में निवेश का भरोसा और मजबूत हो सकता है। सरकार का लक्ष्य विदेशी और घरेलू दोनों तरह के निवेशकों को आकर्षित करना है। सीनियर सिटीजन को लेकर भी बजट में अतिरिक्त राहत की संभावना है। रेलवे टिकट बुकिंग में रियायत, हेल्थकेयर खर्चों में टैक्स छूट और पेंशन से जुड़े सुधार जैसे कदम बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकते हैं। बजट से पहले राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। कांग्रेस ने सरकार पर नीति-निर्माण में तालमेल की कमी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बजट पेश होने के तुरंत बाद जीडीपी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी करने की तैयारी है, जिससे बजट के आंकड़ों में बाद में संशोधन हो सकता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे राज्यों और नीति निर्माताओं के लिए अनिश्चितता बढ़ाने वाला कदम बताया है।

अगर मोदी सरकार के बजट इतिहास पर नजर डालें, तो 2014 से अब तक कई बड़े आर्थिक फैसले लिए गए हैं।

एपस्टीन फाइल्स में पीएम मोदी के इजराइल दौरे का दावा निराधार, विदेश मंत्रालय ने किया सिरे से खंडन

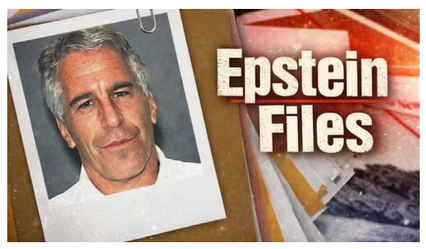

नई दिल्ली। अमेरिका में जारी की गई नई एपस्टीन फाइल्स को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज है और भारत में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया चर्चाओं में यह दावा किया गया कि इन दस्तावेजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2017 के इजराइल दौरे का उल्लेख है। इस दावे के सामने आते ही कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरह से खारिज करते हुए साफ कहा है कि ऐसा कोई भी जिक्र पूरी तरह निराधार, तथ्यहीन और बकवास है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा एक आधिकारिक, सार्वजनिक और ऐतिहासिक राजकीय यात्रा थी, जिसका एपस्टीन या उससे जुड़े किसी भी मामले से कोई लेना-देना नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि एपस्टीन फाइल्स में पीएम मोदी के इजराइल दौरे का उल्लेख होने का दावा पूरी तरह गलत है और इस तरह की अफवाहें फैलाना गैर-जिम्मेदाराना है। मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि भारत सरकार इस तरह के झूठे और भ्रामक दावों को गंभीरता से लेती है और तथ्यों के आधार पर ही प्रतिक्रिया देती है।

दरअसल, अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा हाल ही में जेफरी एपस्टीन से जुड़े मामलों की एक नई और बड़ी खेप सार्वजनिक की गई है। इन फाइल्स में करीब 30 लाख पन्नों के दस्तावेज, 2,000 से ज्यादा वीडियो और लगभग 1 लाख 80 हजार तस्वीरें शामिल बताई जा रही हैं। इनमें कोर्ट रिकॉर्ड, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट, गवाहों के बयान और एपस्टीन के निजी फ्लाइट लॉग जैसे संवेदनशील दस्तावेज शामिल हैं। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद दुनिया भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि इनमें कई प्रभावशाली और चर्चित हस्तियों के नाम सामने आए हैं।

नई फाइल्स में जिन नामों का जिक्र हुआ है, उनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स, टेक उद्योगपति एलन मस्क और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू जैसे बड़े नाम शामिल हैं। दस्तावेजों में कुछ मामलों में गवाहों की गवाही, पुराने संदेश और तस्वीरों का हवाला दिया गया है। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एपस्टीन के कथित संबंधों को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है। कुछ गवाहों ने दावा किया है कि ट्रंप अक्सर एपस्टीन के पाम बीच स्थित घर और उसके निजी क्लब में आते-जाते थे। दस्तावेजों में कुछ तस्वीरों और पुराने मैसेज का भी जिक्र है, जिन्हें दोनों के बीच दोस्ताना संबंधों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इन फाइल्स में यह भी सामने आया है कि एपस्टीन ने कई प्रभावशाली लोगों को अपने निजी द्वीप पर आमंत्रित किया था। एलन मस्क को भी कथित तौर पर कई बार न्योता दिया गया, हालांकि मस्क से जुड़े आरोपों या उनके वहां जाने की पुष्टि को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बिल गेट्स और प्रिंस एंड्रू के नाम पहले भी एपस्टीन विवाद में सामने आ चुके हैं, लेकिन नए दस्तावेजों ने इस मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।

इसी बीच भारत में कुछ राजनीतिक दलों और सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए पीएम मोदी के इजराइल दौरे को एपस्टीन फाइल्स से जोड़ने की कोशिश की गई, जिसे विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया।

गरीबी की बेबसी और सिस्टम की संवेदनहीनता, ठेले पर गया सम्मान

फरीदाबाद। एक ओर देश आधुनिकता, डिजिटल इंडिया और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के दावे करता है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इतनी कठोर है कि मौत के बाद भी गरीब को सम्मान नसीब नहीं होता। फरीदाबाद में 35 वर्षीय अनुराधा देवी की मौत के बाद जो दृश्य सामने आया, उसने न सिर्फ मानवता को झकझोर दिया, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

अनुराधा देवी लंबे समय से टीबी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। इलाज के लिए उनके पति ने अपनी वर्षों की जमा पूंजी खर्च कर दी थी। घर की आर्थिक हालत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया था। इसी बीच अस्पताल में इलाज के दौरान अनुराधा की मौत हो गई। परिवार के लिए यह सिर्फ अपनों को खोने का दुख नहीं था, बल्कि इसके बाद जो हुआ, वह दर्द को और गहरा कर गया।

परिजनों का आरोप है कि बादशाह खान सिविल अस्पताल प्रशासन ने शव को घर ले जाने के लिए न तो शव वाहन उपलब्ध कराया और न ही किसी तरह की वैकल्पिक मदद की। जब परिवार ने एंबुलेंस की मांग की, तो उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया गया। निजी वाहन की बात कही गई और उसका किराया 500 से 700 रुपये बताया गया। गरीबी से जूझ रहे परिवार के लिए यह रकम भी जुटा पाना संभव नहीं था।

अस्पताल परिसर में घंटों तक इधर-उधर भटकने के बाद जब कोई सहारा नहीं मिला, तो मजबूरी में परिवार ने मोटराइज्ड ठेले का सहारा लिया। इसी ठेले पर अनुराधा देवी का शव रखा गया और लगभग 12 किलोमीटर का सफर तय कर उसे घर तक लाया गया। रास्ते भर लोग इस दृश्य को देखते रहे, कोई सहानुभूति जताता रहा, तो कोई खामोशी से आंखें फेरता रहा। यह दृश्य किसी एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की असफलता का प्रतीक बन गया।

दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। शव को घर लाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए भी परिवार के पास पैसे नहीं थे। पड़ोसियों और जान-पहचान वालों से उधार लेकर किसी तरह अंतिम संस्कार किया गया। जिस महिला ने जीवन भर संघर्ष किया, उसे अंतिम विदाई भी कर्ज और मजबूरी के सहारे मिली।

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो लोगों में आक्रोश फैल गया। सवाल उठने लगे कि सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं आखिर कहां हैं। क्या मौत के बाद भी इंसान को इस तरह अपमानित होना पड़ेगा? क्या सरकारी दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं?

मामले के तूल पकड़ने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। सिविल सर्जन ने बताया कि पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और वरिष्ठ डॉक्टरों की एक कमेटी गठित की गई है। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सरकारी एंबुलेंस शव वाहन के रूप में उपयोग नहीं की जाती और शव ले जाने की सुविधा रेड क्रॉस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। हालांकि सवाल यह है कि अगर ऐसी व्यवस्था है, तो उस वक्त परिवार को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई और क्यों उन्हें इतनी अमानवीय स्थिति का सामना करना पड़ा।

यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि नीतियों और जमीनी सच्चाई के बीच गहरी खाई है। गरीब मरीजों के इलाज और मृत्यु के बाद की प्रक्रिया को लेकर सरकारी अस्पतालों में संवेदनशीलता और जवाबदेही की सख्त जरूरत है। अनुराधा देवी का ठेले पर ले जाया गया शव सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर एक कड़ा सवाल है, जो जीवन ही नहीं, मृत्यु के सम्मान की भी गारंटी नहीं दे पा रही।

वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की राह: रघुराम राजन की चेतावनी और भविष्य की रणनीति

दुनिया आज जिस दौर से गुजर रही है, वह केवल आर्थिक मंदी या भू-राजनीतिक तनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, सहयोग और दीर्घकालिक सोच की भी परीक्षा है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इसी पृष्ठभूमि में दुनिया को "बेहद खतरनाक और चुनौतीपूर्ण दौर" से गुजरता हुआ बताया है। उनका यह बयान किसी एक देश या सरकार पर टिप्पणी नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की मौजूदा दिशा पर एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। राजन का मानना है कि भारत के लिए यह समय बेहद निर्णायक है, जहां तात्कालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक दृष्टि अपनाना ही देश को स्थिर और मजबूत बना सकता है। रघुराम राजन ने 2026-27 के बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से विशेष अपेक्षा जताई है। उनका कहना है कि आने वाला बजट सिर्फ अगले एक या दो साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की चुनौतियों और संभावनाओं को देखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, भारत को ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए जो न केवल तेज गति से आगे बढ़े, बल्कि संकटों के सामने टिकाऊ और आत्मनिर्भर भी हो। राजन का यह दृष्टिकोण उस सोच से अलग है, जिसमें केवल विकास दर, घाटा या तात्कालिक निवेश के आंकड़ों को सफलता का पैमाना माना जाता है।

राजन इस बात पर जोर देते हैं कि भारत को दुनिया में एक भरोसेमंद मित्र और साझेदार के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके शब्दों में, "हम एक लचीली, स्वतंत्र और तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था की ओर कैसे बढ़ें, इस पर ध्यान देना होगा, ताकि दुनिया भारत को मित्र माने।" यह बयान ऐसे समय आया है जब वैश्विक स्तर पर देशों के बीच अविश्वास बढ़ रहा है, व्यापारिक बाधाएं खड़ी हो रही हैं और सप्लाई चेन बार-बार टूट रही हैं। ऐसे में भारत के पास मौका है कि वह अपनी नीतियों और व्यवहार से खुद को एक स्थिर और जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित करे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को लेकर भी रघुराम राजन का नजरिया संतुलित है। वे इसे भविष्य का बड़ा अवसर मानते हैं, लेकिन आंख मूंदकर अपनाने के खिलाफ चेतावनी भी देते हैं। उनका कहना है कि AI में निवेश निश्चित रूप से रोमांचक है और इससे उत्पादकता, सेवाओं और नवाचार में बड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन इसमें जोखिम भी कम नहीं हैं। यदि हम कुछ गिनी-चुनी संस्थाओं या कंपनियों पर अत्यधिक निर्भर हो गए, तो यह भविष्य में गंभीर समस्या बन सकता है। खासकर तब, जब हमारे पास पास के समृद्ध और बड़े बाजारों की कमी हो, जिन्हें हम बड़े पैमाने पर सप्लाई कर सकें।

राजन का तर्क है कि तकनीक तभी फायदेमंद होती है, जब उसके साथ मजबूत संस्थान, कुशल मानव संसाधन और विविध बाजार जुड़े हों। केवल तकनीक के भरोसे विकास की उम्मीद करना एक तरह का भ्रम हो सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने की जरूरत है, ताकि क्षेत्रीय स्तर पर एक ऐसा बाजार तैयार हो सके, जो वैश्विक उतार-चढ़ाव के समय सहारा बन सके।

पड़ोसी देशों को लेकर रघुराम राजन की सोच बेहद व्यावहारिक है। उन्होंने बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों के साथ मजबूत संबंधों की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना है कि भारत की भौगोलिक स्थिति उसे यह अवसर देती है कि वह दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग का केंद्र बने। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में भारत के पास विस्तार की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए क्षेत्रीय सहयोग और विश्वास बेहद जरूरी है। यदि पड़ोसी देश आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तो भारत के लिए भी नए बाजार और अवसर खुलेंगे।

राजन ने यह भी स्वीकार किया कि भारत के कई राज्यों ने निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियां बनाकर सकारात्मक पहल की है। कुछ राज्यों में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल, सरल नियम और बुनियादी ढांचे पर जोर देखने को मिलता है। लेकिन उनके अनुसार, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। केवल कुछ चुनिंदा राज्यों की सफलता से देश की पूरी तस्वीर नहीं बदलती। जरूरी है कि विकास का लाभ व्यापक रूप से फैले और हर क्षेत्र तक पहुंचे।

चीन का उदाहरण देते हुए रघुराम राजन ने एक अहम चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत को चीन की गलतियों से सीखना चाहिए। चीन ने पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर निवेश और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया, लेकिन उनमें से कई परियोजनाएं अब बोझ बनती जा रही हैं। अस्थिर निवेश और असेट मार्केट की समस्याएं चीन के सामने गंभीर चुनौती बन चुकी हैं और उनसे उबरने में कई साल लग सकते हैं। राजन का कहना है कि भारत को इस तरह के अव्यवहारिक और दिखावटी निवेश से बचना चाहिए।

उन्होंने विशेष रूप से अत्यधिक सार्वजनिक निवेश पर सवाल उठाए। हर शहर में मेट्रो, फ्लाईओवर या बड़े आवासीय प्रोजेक्ट बनाना विकास का प्रतीक नहीं होता। अगर इन परियोजनाओं का वास्तविक उपयोग नहीं है, तो वे केवल सरकारी संसाधनों पर बोझ बनती हैं। राजन के अनुसार, बुनियादी ढांचा वही बनना चाहिए, जिसकी जनता को सच में जरूरत हो और जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर हो सके। विकास का मतलब केवल कंक्रीट और स्टील नहीं, बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार है।

बजट सुधार को लेकर रघुराम राजन की मांग स्पष्ट है। वे चाहते हैं कि आगामी बजट अल्पकालिक आंकड़ों और राजनीतिक दबावों से ऊपर उठकर तैयार किया जाए। राजकोषीय लक्ष्यों का महत्व है, लेकिन यदि केवल घाटा या खर्च के आंकड़ों पर ही ध्यान दिया गया, तो लंबे समय में अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। उनके अनुसार, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सोच-समझकर किया गया खर्च ही देश को भविष्य के लिए तैयार करेगा।

राजन का यह भी मानना है कि भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में गहराई से जुड़ने की जरूरत है। इसके लिए न केवल नीतिगत सुधार चाहिए, बल्कि भरोसेमंद प्रशासन, स्थिर कानून व्यवस्था और पारदर्शिता भी जरूरी है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

परिपक्व उम्र में ही हो सोशल मीडिया तक पहुंच

बच्चों व किशोरों की सोशल मीडिया पर बढ़ती अति-सक्रियता अभिभावकों ही नहीं, देश के लिये भी एक गंभीर चिंता का विषय है। छात्रों का पढ़ाई से भटकाव व एकाग्रता में गिरावट समय की बड़ी फिक्र है। इसी बीच इकोनॉमिक सर्वे में सोशल मीडिया तक उम्र के हिसाब से पहुंच का सुझाव एक स्वागत योग्य कदम है। सालों से, डिजिटल विस्तार को एक बिना शर्त अच्छे बदलाव के रूप में देखा जाता रहा है। कहा जाता रहा है कि सोशल मीडिया तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने, डिजिटल लिटरेसी की खामियों को दूर करने और शिक्षा को आधुनिक बनाने में डिजिटल क्रांति सहायक है। निश्चित रूप से आर्थिक सर्वे में इस बाबत उल्लेख एक असहज करने वाली सच्चाई को संतुलित करने का प्रयास करता है। यह स्वीकार किया जा रहा है कि बिना रोक-टोक के डिजिटल एक्सपोजर तेजी से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बनता जा रहा है। सही मायनों में डिजिटल लत को मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षणिक प्रदर्शन और उत्पादकता को प्रभावित करने वाली समस्या के रूप मे पहचानते हुए, सर्वे इस बहस को तथ्यों पर आधारित नीति बनाने की जरूरत बताता है। इसकी सिफारिश है कि उम्र के हिसाब से एक्सेस की सीमाएं तय करने, उम्र की वेरिफिकेशन के लिये प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही निर्धारित करने, बच्चों के लिये सरल डिवाइस बनाने और ऑनलाइन कक्षाओं पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता है। सही मायनों में इस मुद्दे पर वैश्विक सहमति का ही अनुसरण किया जा रहा है। वास्तव में बच्चों को सम्मोहित करने वाले डिजिटल डिजाइनों से उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी जरूरत है। जो कोमल मन-मस्तिष्क वाले बच्चों पर खासा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। निश्चित रूप से डिजिटल लत के शिकार होते बच्चों व किशोरों के, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्धारण समय की मांग है। इसके अलावा इस बाबत सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देना भी उतना ही जरूरी है। तभी इस संकट का आशाजनक समाधान तलाशना संभव हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर, इस संकट से उबरने के लिये प्लेटफॉर्म लेवल सेफ्टी और फैमिली डेटा प्लान की भी मांग की जा रही है। जो पढ़ाई की जरूरत और मनोरंजन के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल का फर्क कर सके। इसके साथ ही हालिया आर्थिक सर्वे में इस बात को स्वीकार किया गया है कि माता-पिता पहले से ही यह जानते हैं कि व्यक्तिगत कंट्रोल बड़े पैमाने से इस समस्या का समुचित हल नहीं निकाल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रयास इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। यही वजह है कि आस्ट्रेलिया व फ्रांस जैसे विकसित देशों में सरकारों को इस दिशा में सख्त पहल करनी पड़ी। एक ओर जहां आस्ट्रेलिया ने सोलह साल से कम उम्र वाले बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच पर रोक लगायी है, वहीं फ्रांस ने पंद्रह साल से कम उम्र वाले बच्चों की सोशल मीडिया तक सीधी पहुंच को रोकने को कदम उठाये हैं। कुछ अन्य देशों में भी सरकारें तेजी से सख्त सीमाएं तय करने की दिशा में काम कर रही हैं। आज जहां भारत में स्मार्टफोन के इस्तेमाल की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। वैसे भारत जैसे देश जहां युवाओं की आबादी बहुत ज्यादा है, वहां डिजिटल क्रांति से पूरी तरह अलग भी नहीं रहा जा सकता। ऐसे में एक नियम से ही सबको नियंत्रित करना संभव नहीं होगा। इसके बावजूद हमें स्वीकारना होगा कि विदेशी प्लेटफॉर्मों से प्रसारित अपसंस्कृति भारतीय किशोरों को पथभ्रष्ट करने में घातक भूमिका निभा रही है। जिससे देश में किशोरों की यौन अपराधों में संलिप्तता का खतरा बढ़ रहा है। ये अपसंस्कृति न केवल समय से पहले बच्चों को वयस्क बना रही है, बल्कि उनमें मानवीय संवेदनाओं का भी क्षरण कर रही है। जो किसी भी सभ्य समाज के लिये एक गंभीर चुनौती है। खासकर भारत जैसे देश में जहां सांस्कृतिक मूल्यों व संबंधों में शुचिता को हमेशा प्राथमिकता दी जाती रही है। इस बाबत सरकार की सख्त पहल और अभिभावकों की सजगता मिलकर ही समस्या का समाधान निकाल सकती है।

टैरिफ के बावजूद आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका से आगे निकलता शेष विश्व

> “ अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले आयात पर लगाए गए टैरिफ के पश्चात अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कम होती हुई दिखाई दे रही है। वर्ष 2024 में अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत की रही थी जो वर्ष 2025 में घटकर 2.1 प्रतिशत हो गई।

दिनांक 20 जनवरी 2025 को डॉनल्ड ट्रम्प अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनाए गए थे। वर्ष 2024 में ट्रम्प ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव “Make America Great Again” अर्थात “अमेरिका को पुनः महान बनाएं”, नारे के साथ जीता था। वर्ष 2025 का पूरा वर्ष भर पूरे विश्व ने ट्रम्प को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए देखा। लगभग पूरा 2025 का वर्ष ट्रम्प ने विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले उत्पादों के आयात पर टैरिफ लगाते हुए बिताया और मित्र देशों सहित कई देशों से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर भारी भरकम टैरिफ लगाए। ट्रम्प का सोचना था कि टैरिफ को बढ़ाकर वे अन्य देशों से अमेरिका को होने वाले निर्यात को कम करेंगे और इससे अमेरिका में ही इन उत्पादों का उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा। ट्रम्प का संभवतः यह सोचना था कि उनका यह प्रयास अमेरिका को महान बनाते हुए शेष विश्व को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। परंतु, वर्ष 2025 में अमेरिका एवं शेष विश्व के आर्थिक क्षेत्र के आंकडें देखने पर ध्यान में आता है कि अमेरिका के मित्र राष्ट्रों सहित विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ का असर अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर लगभग नहीं के बराबर पड़ा है। बल्कि, इसका खामियाजा अमेरिका के नागरिकों को भुगतना पड़ा है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से अमेरिका में उत्पादों की कीमतों में बेतहाशा बृद्धि दर्ज हुई है, इससे मुद्रा स्फीति में वृद्धि तेज हुई है एवं अमेरिकी नागरिकों को विभिन्न उत्पादों को बढ़ी हुई कीमतों दरों पर खरीदना पड़ रहा है। अमेरिकी नागरिक पिछले 5 वर्षों की तुलना में आज खाद्य सामग्री पर 30 प्रतिशत अधिक खर्च कर रहे हैं। अमेरिका में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें 22 प्रतिशत से बढ़ चुकी हैं। खाद्य पदार्थों एवं मकान की कीमतों में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई हैं। अमेरिका में मुद्रा स्फीति की दर भी 3 से 4 प्रतिशत के बीच बनी हुई है, जो पिछले कई वर्षों की तुलना में बहुत अधिक है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से परेशान हो रहा है अमेरिकी नागरिक, न कि अन्य कोई देश। श्री रुचिर शर्मा, भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक एवं फायनैन्शल टाइम्स के स्तम्भ लेखक, ने अपने एक साक्षात्कार में कई आंकडें दिए हैं, जिनका प्रयोग इस लेख को तैयार करने में किया गया है। अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले आयात पर लगाए गए टैरिफ के पश्चात अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कम होती हुई दिखाई दे रही है। वर्ष 2024 में अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत की रही थी जो वर्ष 2025 में घटकर 2.1 प्रतिशत हो गई। जबकि वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर दोनों वर्षों, 2024 एवं 2025, में 2.8 प्रतिशत बनी रही है। वर्ष 2025 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में किसी प्रकार की कमी दृष्टिगोचर नहीं हुई है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2024 में वृद्धि दर, 6.5 प्रतिशत की रही थी, जो वर्ष वर्ष 2025 में बढ़कर 7.2 प्रतिशत की हो गई। वर्ष 2024 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से 52 प्रतिशत देशों की प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद में वृद्धि दर अमेरिका की तुलना में अधिक रही थी जबकि वर्ष 2025 में 76 प्रतिशत देशों की प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद में वृद्धि दर अमेरिका की तुलना में अधिक रही है। वर्ष 2025 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास दर तेज गति बढ़ती हुई पाई गई है। इस प्रकार, अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ के बावजूद शेष विश्व में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर अमेरिका से अधिक रही है। इस प्रकार अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का प्रभाव अन्य देशों के विकास पर विपरीत रूप से नहीं पड़ा है।

अमेरिका के पूंजी (शेयर) बाजार में भी वर्ष 2025 में निवेशकों को अपने निवेश पर कम आय प्राप्त हुई है। अमेरिका में निवेशकों द्वारा पूंजी (शेयर) बाजार में किए गए निवेश पर 18 प्रतिशत की आय का अर्जन हुआ है। जबकि, यूरोप में निवेशकों को 35 प्रतिशत, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में निवेशकों को 34 प्रतिशत, अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व में निवेशकों को 32 प्रतिशत एवं चीन में निवेशकों को 31 प्रतिशत की आय अर्जित हुई है। इस प्रकार, अमेरिका की तुलना में अन्य देशों में पूंजी (शेयर) बाजार में निवेशकों को लगभग दुगनी आय अर्जित हुई है। अमेरिकी नागरिकों का पूंजी (शेयर) बाजार में निवेश तुलनात्मक रूप से अधिक है। अमेरिकी नागरिकों का जायदाद में निवेश 30 प्रतिशत है जबकि शेयर बाजार में 32 प्रतिशत निवेश है। चीन के नागरिकों का जायदाद में निवेश 55 प्रतिशत एवं शेयर बाजार में निवेश केवल 11 प्रतिशत है। इसी प्रकार, यूरोप के नागरिकों का निवेश क्रमशः 57 प्रतिशत एवं 16 प्रतिशत है। भारतीय नागरिकों के निवेश क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 7 प्रतिशत है। अमेरिका द्वारा अन्य देशों से अमेरिका में होने वाले आयात पर लगाए गए टैरिफ के चलते अमेरिका का राजकोषीय घाटा वर्ष 2024 के सकल घरेलू उत्पाद के 6.9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2025 में 6 प्रतिशत हो गया है। एक रीसर्च प्रतिवेदन में यह तथ्य उभरकर भी सामने आया है कि टैरिफ के कारण अमेरिका में उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हुई है एवं टैरिफ का लगभग 96 प्रतिशत भाग अमेरिकी नागरिकों द्वारा वहन किया गया है। इसके कारण अन्य देशों से अमेरिका को निर्यात कम नहीं हुए हैं। यूरोप का राजकोषीय घाटा वर्ष 2024 के 3.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में 3.2 प्रतिशत हो गया है। उभर रही अर्थव्यवस्थाओं का राजकोषीय घाटा वर्ष 2024 के 4.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में 4.8 प्रतिशत हो गया है। पूर्व में विभिन्न देशों का राजकोषीय घाटा लगभग 3 प्रतिशत तक रहता आया है जबकि वर्तमान परिस्थितियों के मध्य, विभिन्न देशों का राजकोषीय घाटा बढ़ते हुए 6 प्रतिशत के स्तर तक रहने लगा है। यह स्थिति वित्तीय क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

वर्ष 2025 में विदेशी व्यापार में वृद्धि दर भी अमेरिका की तुलना में अन्य देशों में अधिक रही है। अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व के निर्यात में वर्ष 2019 से 2024 के दौरान औसत 5 प्रतिशत की वृद्धि रही थी जो वर्ष 2025 में बढ़कर 6.4 प्रतिशत की हो गई है। जबकि अमेरिका से निर्यात में वृद्धि दर इसी अवधि के दौरान 4.6 प्रतिशत से गिरकर 4.1 प्रतिशत रह गई है। टैरिफ का अमेरिका से अन्य देशों को होने वाले निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ा है जबकि अन्य देशों ने आपस में नए बाजारों की तलाश करते हुए अपने विदेशी व्यापार, विशेष रूप से निर्यात, में वृद्धि दर्ज की है। कई देशों ने आपस में मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न किए हैं, इससे भी विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में वृद्धि दर्ज हुई है। अमेरिका से अन्य देशों को निर्यात के कम होने के चलते अमेरिका में चालू व्यापार खाता घाटा 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका में आज भी उत्पादन की तुलना में उपभोग बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है।

अमेरिका की टैरिफ नीति के चलते अमेरिका पुनः महान (MAGA) बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु, विश्व के अन्य कई देश जरूर महान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अतः टैरिफ का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को विपरीत रूप से प्रभवित करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि विश्व में अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार, ट्रम्प इस धरा को महान बनाने (Make Earth Great Again - MEGA) में अपना योगदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वैश्विक स्तर पर विपरीत परिस्थितियों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारत का राजकोषीय घाटा प्रति वर्ष लगातार कम हो रहा है। यह वर्ष 2024 में 5.5 प्रतिशत था, जो वर्ष 2025 में 4.8 प्रतिशत हो गया एवं अब वर्ष 2026 में घटकर 4.4 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। भारत को यदि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बनाना है तो हमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 12 से 14 प्रतिशत वृद्धि के स्तर को प्राप्त करना होगा, जैसा कि चीन ने लम्बे समय तक अपनी अर्थव्यवस्था को इस दर पर आगे बढ़ाने में सफलता अर्जित की थी। सकल घरेलू उत्पाद में यह महत्वाकांक्षी वृद्धि दर हासिल करना कोई असम्भव कार्य नहीं है। अमेरिका यदि भारत का सहयोग करने को तैयार नहीं है तो भारत को अन्य बाजार तलाशते हुए विभिन्न उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना होगा। आज भारतीय अर्थव्यस्था मुख्यतः आंतरिक उपभोग पर आधारित है, जबकि उत्पादों के निर्यात को भी आज तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत द्वारा निर्यात के सामर्थ्य का उपयोग बहुत कम स्तर पर किया है।

प्रेरणा

जब समय स्वयं जल को निर्मल करता है

मनुष्य का जीवन यात्राओं से भरा हुआ है—कभी बाहरी यात्राएँ, तो कभी भीतर की। इन्हीं यात्राओं के बीच हमें ऐसे क्षण मिलते हैं, जो देखने में छोटे लगते हैं, पर अर्थ में विराट होते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक सरल-सी घटना इसी विराट अर्थ को उजागर करती है। यह घटना हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ क्षणिक होती हैं, जबकि प्रकृति स्थायी, शांत और अंततः विजयी रहती है।

धर्मयात्रा पर चलते-चलते जब बुद्ध को थकान हुई, तो उन्होंने एक वृक्ष की छाया में विश्राम किया। वृक्ष, छाया और मौन—ये तीनों प्रकृति की गोद का संकेत हैं, जहाँ मनुष्य स्वयं को पुनः संतुलित करता है। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनन्द से कहा कि वे निकट के झरने से जल ले आएँ। आनन्द आज्ञाकारी थे, वे तुरंत झरने की ओर बढ़े। पर वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि कुछ देर पहले गुज़री एक बैलगाड़ी के कारण पानी मटमैला हो गया था। जल, जो जीवन का प्रतीक है, अस्थायी रूप से अपनी शुद्धता खो बैठा था। यह दृश्य केवल एक झरने का नहीं, बल्कि हमारे जीवन का प्रतिबिंब है। जब बाहरी घटनाएँ घटती हैं—कोई अपमान, कोई असफलता, कोई अप्रत्याशित आघात—तो हमारा मन भी वैसा ही गंदला हो जाता है। आनन्द ने स्वच्छ जल की खोज में अन्यत्र जाने का विचार किया, जैसे हम भी अक्सर कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए रास्ता बदल लेते हैं। पर बुद्ध ने उन्हें रोका और कहा कि वे धैर्य रखें और उसी झरने से जल लाएँ। यह निर्देश साधारण नहीं था; इसमें जीवन का एक गूढ़ रहस्य छिपा था।

कुछ समय बाद आनन्द पुनः झरने पर पहुँचे। इस बार दृश्य बदला हुआ था। गंदला पानी बह चुका था, और झरना फिर से निर्मल होकर बह रहा था। आनन्द ने प्रसन्नता से जल भरा और बुद्ध के पास लौटे। तब बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा कि जीवन में परिस्थितियों को नहीं, प्रकृति को देखना चाहिए। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, पर प्रकृति स्थिर रहती है। यही वाक्य इस पूरी कथा का केंद्र है। परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण में नहीं होतीं। वे बाहरी कारकों से बनती हैं और समय के साथ बदल जाती हैं। कभी हम सफलता के शिखर पर होते हैं, तो कभी निराशा की गहराइयों में। यदि हम हर परिस्थिति के साथ स्वयं को बदलते रहें, तो हमारी कोई स्थायी पहचान नहीं बचती। इसके विपरीत, प्रकृति—चाहे वह झरने की हो या मनुष्य की—अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ती। झरने का स्वभाव बहना और निर्मल रहना है, भले ही बीच में उसे गंदला कर दिया जाए। उसी तरह मनुष्य का मूल स्वभाव भी यदि सत्य, करुणा और विवेक से बना है, तो अस्थायी कठिनाइयाँ उसे स्थायी रूप से दूषित नहीं कर सकतीं।

आज का समय अत्यंत तेज़ है। हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है। थोड़ी-सी बाधा आते ही लोग हताश हो जाते हैं, अपने सिद्धांत छोड़ देते हैं या गलत मार्ग चुन लेते हैं। यह कथा हमें ठहरना सिखाती है। ठहरना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी समझ का संकेत है। जो व्यक्ति समय को अपना कार्य करने देता है, वह स्वयं को अनावश्यक संघर्ष से बचा लेता है। जैसे गंदला जल स्वयं बह गया, वैसे ही जीवन की उलझनें भी समय के साथ सुलझ जाती हैं, यदि हम अपनी मूल शुद्धता बनाए रखें। इस कथा में संस्कारों की भूमिका भी स्पष्ट होती है। बुद्ध कहते हैं कि यदि मनुष्य में सुसंस्कार और श्रेष्ठ गुण हैं, तो वे दीर्घकाल में स्वयं महकते हैं। यह महक किसी प्रचार की मोहताज नहीं होती। ईमानदारी, धैर्य, परिश्रम और करुणा ऐसे गुण हैं, जिन्हें कभी-कभी तुरंत पहचान नहीं मिलती, पर समय आने पर वही गुण व्यक्ति को विशिष्ट बनाते हैं। प्रकृति का नियम है कि वह अंततः संतुलन स्थापित करती है। जो अस्थायी रूप से आगे दिखता है, वह हमेशा श्रेष्ठ हो, यह आवश्यक नहीं।

मनुष्य अक्सर दूसरों से तुलना करके स्वयं को आंकता है। यह तुलना भी एक तरह की परिस्थिति है, जो मन को अशांत करती है। यदि हम अपनी प्रकृति पर विश्वास रखें और अपने मार्ग पर शांतिपूर्वक चलते रहें, तो तुलना का बोझ स्वतः हल्का हो जाता है। झरना यह नहीं सोचता कि कौन सा नदी उससे आगे बह रही है; वह बस अपने स्वभाव के अनुसार बहता रहता है।

यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान तुरंत प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सही समय पर की गई प्रतिक्रिया है। आनन्द यदि पहले ही प्रयास में जल लेने पर अड़े रहते या झरने को साफ़ करने का प्रयास करते, तो शायद जल और अधिक गंदला हो जाता। कभी-कभी हस्तक्षेप समस्या को बढ़ा देता है। विवेक यही है कि कब प्रयास करना है और कब प्रतीक्षा।

अंत में, यह कथा आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है। जब हम अपनी प्रकृति पर भरोसा करते हैं, तो हमें हर परिस्थिति से डर नहीं लगता। हमें पता होता है कि यह भी गुजर जाएगी। यही विश्वास मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। यदि हम जीवन में प्रकृति की इस प्रबलता को समझ लें, तो हम अस्थायी उतार-चढ़ावों से विचलित हुए बिना एक संतुलित, शांत और सार्थक जीवन जी सकते हैं। समय स्वयं जल को निर्मल कर देता है—बस हमें धैर्य रखना और अपनी मूल शुद्धता को संभाले रखना होता है।

आर्थिक सर्वेक्षण से बजट तक: भविष्य के भारत की तलाश

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद के पटल पर प्रस्तुत किया जाने वाला बजट केवल आय-व्यय का वार्षिक लेखा-जोखा नहीं होता, बल्कि वह देश की आर्थिक दिशा, सामाजिक प्राथमिकताओं और भविष्य की संभावनाओं का दर्पण होता है। आज जब भारत एक ओर तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व मंच पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है और दूसरी ओर वैश्विक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनावों, जलवायु संकट और तकनीकी परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब यह बजट और भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। व्यक्तिगत नागरिक से लेकर व्यापारी, उद्योगपति, किसान, श्रमिक, युवा और मध्यम वर्ग-सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हैं, क्योंकि इससे न केवल वर्तमान वर्ष की आर्थिक तस्वीर, बल्कि “भविष्य के भारत” की झलक भी मिलती है। बजट से पूर्व प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण ने सरकार की सोच और नीति-दृष्टि के कई संकेत दिए हैं। इसमें विकास को केवल आंकड़ों की वृद्धि तक सीमित न रखकर अवसरों के विस्तार, समावेशी विकास और दीर्घकालिक स्थिरता पर जोर दिया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां अवश्य हैं, किंतु उनसे अधिक संभावनाएं हैं। यही दृष्टिकोण इस बजट का मूल स्वर होना चाहिए-चुनौतियों को अवसरों में बदलने का साहसिक प्रयास।

सबसे पहली और महत्वपूर्ण अपेक्षा निम्न वर्ग की क्रय-शक्ति बढ़ाने को लेकर है। किसी भी अर्थव्यवस्था की वास्तविक मजबूती तभी आती है जब उसके सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी सम्मानजनक जीवन जी सके और उपभोग में भागीदार बने। यदि निम्न आय वर्ग की आय बढ़ती है, उसे सस्ती और सुलभ सुविधाएं मिलती हैं, तो उसका सीधा प्रभाव मांग पर पड़ता है और मांग बढ़ने से उत्पादन, निवेश और रोजगार-तीनों को गति मिलती है। इसलिए इस बजट में प्रत्यक्ष नकद अंतरण, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च के साथ-साथ रोजगार सृजन के ठोस उपाय अपेक्षित हैं। मनरेगा जैसे कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण, शहरी गरीबों के लिए भी समान प्रकृति की योजनाएं और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

शहरी विकास इस बजट का एक और प्रमुख केंद्र होना चाहिए। भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है और शहरों पर जनसंख्या, आवास, परिवहन, जल, स्वच्छता और पर्यावरण का दबाव लगातार बढ़ रहा है। केवल बड़े महानगरों पर निर्भरता अब व्यावहारिक नहीं रही। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा द्वारा सुझाया गया शहरी विकेंद्रीकरण का विचार आज के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। छोटे और मध्यम शहरों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाना, उद्योगों और सेवाओं को वहां प्रोत्साहित करना, न केवल महानगरों पर बोझ कम करेगा बल्कि क्षेत्रीय असंतुलन को भी घटाएगा। बजट में यदि टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए विशेष शहरी अवसंरचना पैकेज, परिवहन नेटवर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी और कौशल विकास योजनाएं लाई जाती हैं, तो यह दूरगामी परिवर्तन का आधार बन सकता है।

वैश्विक स्तर पर टैरिफ, व्यापार अवरोध और संरक्षणवाद की प्रवृत्तियां भारत के लिए चुनौती भी हैं और अवसर भी। अजय बंगा का यह कथन कि टैरिफ पर अधिक चिंता करने के बजाय व्यापारिक अवसरों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, भारत की वर्तमान स्थिति के लिए उपयुक्त दृष्टि प्रदान करता है। भारत के पास विशाल घरेलू बाजार, युवा जनसंख्या, डिजिटल क्षमताएं और उद्यमशीलता की प्रबल ऊर्जा है। यदि यह बजट निर्यात-उन्मुख उद्योगों, स्टार्ट-अप्स, मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू-एडेड सेक्टर को प्रोत्साहन देता है, तो भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में और मजबूत स्थान बना सकता है। ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ को केवल नारों से आगे ले जाकर व्यावहारिक नीति समर्थन की आवश्यकता है-सरल कर संरचना, आसान ऋण, अनुसंधान एवं नवाचार में निवेश और व्यापार करने में सुगमता के माध्यम से।

इस संदर्भ में मध्यम वर्ग की भूमिका को नजरअंदाज करना आर्थिक दृष्टि से आत्मघाती होगा। मध्यम वर्ग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है-वह सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा करदाता भी। विडंबना यह है कि बजट चर्चाओं में अक्सर यही वर्ग अपेक्षाकृत उपेक्षित रह जाता है। बढ़ती महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च, आवास ऋण और करों का बोझ मध्यम वर्ग की बचत और उपभोग दोनों को प्रभावित करता है। यदि इस बजट में आयकर स्लैब में तर्कसंगत सुधार, शिक्षा-स्वास्थ्य पर कर राहत और आवास को प्रोत्साहन जैसे कदम उठाए जाते हैं, तो इससे न केवल मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी बल्कि मांग-आधारित विकास को भी बल मिलेगा।

उद्योगों और व्यापार जगत के लिए बजट से अपेक्षा है कि वह स्थिर और पूर्वानुमेय नीति वातावरण प्रदान करे। निवेशक अनिश्चितता से डरते हैं। कर नीति में बार-बार बदलाव, अनुपालन की जटिलता और नियामक अस्पष्टता निवेश को बाधित करती है। इस बजट में यदि दीर्घकालिक कर-नीति का स्पष्ट संकेत, एमएसएमई सेक्टर के लिए सस्ता ऋण, तकनीकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहन और हरित उद्योगों के लिए विशेष पैकेज दिए जाते हैं, तो यह उद्योगों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र, जो रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है, उसे आर्थिक पुनरुत्थान का केंद्र बनाया जाना चाहिए।

अभियान

जब जीवन की बागडोर आपके हाथों में हो: टैरो का ‘द मैजिशियन’ और भाग्य का जागरण

भविष्य को जानने की जिज्ञासा मनुष्य के स्वभाव में सदियों से रही है। कभी यह जिज्ञासा तारों की चाल में उत्तर खोजती है, कभी अंकों के रहस्य में, तो कभी हथेली की रेखाओं में छिपे संकेतों को पढ़ने का प्रयास करती है। जन्मकुंडली, न्यूमेरोलॉजी और हस्तरेखा विज्ञान के साथ-साथ एक ऐसी रहस्यमयी विधा भी है, जिसने आधुनिक समय में लोगों का ध्यान तेजी से आकर्षित किया है—टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर छिपी संभावनाओं, मानसिक स्थितियों और आने वाले अवसरों का दर्पण भी माना जाता है। टैरो काड्र्स में मौजूद प्रतीक, रंग, अंक और पंचतत्व—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—मानव जीवन की सूक्ष्म ऊर्जा को दर्शाते हैं।

टैरो कार्ड ताश के पत्तों जैसे दिखते जरूर हैं, लेकिन उनका अर्थ साधारण नहीं होता। हर कार्ड पर बने चित्र और चिह्न गहरे प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। यही प्रतीक टैरो रीडर को यह समझने में मदद करते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में कौन-सी ऊर्जा सक्रिय है और भविष्य की दिशा किस ओर बढ़ रही है। टैरो के डेक में कई कार्ड होते हैं, जिनमें मेजर आर्काना और माइनर आर्काना शामिल हैं। मेजर आर्काना के कार्ड विशेष रूप से जीवन के बड़े मोड़ों, आत्मिक विकास और भाग्य से जुड़े माने जाते हैं। इन्हीं मेजर आर्काना में एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली कार्ड है—‘द मैजिशियन’।

जब टैरो रीडिंग में ‘द मैजिशियन’ कार्ड निकलता है, तो इसे सफलता और सौभाग्य का मजबूत संकेत माना जाता है। यह कार्ड इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति के पास वह सभी साधन, कौशल और ऊर्जा मौजूद है, जिनकी मदद से वह अपने लक्ष्य को साकार कर सकता है। ‘द मैजिशियन’ को मेगस भी कहा जाता है। यह कार्ड सृजन, नियंत्रण और चेतन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह बताता है कि अब परिस्थितियाँ व्यक्ति के नियंत्रण में आने वाली हैं और वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बनने की स्थिति में है।

‘द मैजिशियन’ कार्ड की छवि अपने-आप में बेहद अर्थपूर्ण होती है। इसमें एक युवा पुरुष या जादूगर को दिखाया जाता है, जिसके एक हाथ से आकाश की ओर और दूसरे हाथ से धरती की ओर इशारा किया गया होता है। यह संकेत देता है कि वह आकाशीय ऊर्जा को धरती पर उतारने की क्षमता रखता है। यानी विचारों और कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने की शक्ति। उसके सामने मेज पर चार प्रतीक रखे होते हैं—छड़ी, तलवार, कप और पेंटाकल—जो चार तत्वों और चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह दर्शाता है कि ‘द मैजिशियन’ सभी संसाधनों का संतुलित उपयोग करना जानता है।

यह कार्ड अक्सर कौशल, बुद्धिमत्ता, चालाकी, संवाद क्षमता और रणनीतिक सोच से जुड़ा माना जाता है। ‘द मैजिशियन’ केवल मेहनत का नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने का भी प्रतीक है। यह व्यक्ति की उस क्षमता को दर्शाता है, जिससे वह अवसरों को पहचानकर उन्हें अपने पक्ष में मोड़ सकता है। टैरो के अनुसार, यह कार्ड बताता है कि व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने प्रयासों और इच्छाशक्ति से परिस्थितियों को बदलने में सक्षम है।

‘द मैजिशियन’ को कभी-कभी हेराफेरी और चतुराई का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन नकारात्मक अर्थ में नहीं। इसका मतलब है कि व्यक्ति स्थितियों को समझकर, कूटनीति और बुद्धि से काम लेना जानता है। वह साम-दाम-दंड-भेद जैसी नीतियों को संतुलन में रखकर अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है। यही कारण है कि यह कार्ड व्यापार, करियर, राजनीति और रचनात्मक क्षेत्रों में विशेष सफलता का संकेत देता है।

इस कार्ड की एक और खास बात यह है कि यह व्यक्ति की बेचैनी और सक्रियता को भी दर्शाता है। ‘द मैजिशियन’ कभी स्थिर नहीं रहता। वह निरंतर सीखने, प्रयोग करने और आगे बढ़ने की सोच रखता है। उसे नई सूचनाएँ, नए विचार और नई संभावनाएँ आकर्षित करती हैं। यही बेचैनी वास्तव में उसकी ताकत बन जाती है, क्योंकि यह उसे जड़ नहीं होने देती। वह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाली ऊर्जा की तरह है—सदैव गतिशील, सदैव सक्रिय।

टैरो रीडिंग में जब यह कार्ड आता है, तो यह संदेश देता है कि अब समय है खुद पर भरोसा करने का। यह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ‘द मैजिशियन’ यह बताता है कि व्यक्ति को बाहर से किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके भीतर ही वह शक्ति मौजूद है, जिससे वह अपने जीवन को दिशा दे सकता है। यह कार्ड नए अवसरों, नए उद्यमों और नई शुरुआत का संकेत देता है। यदि कोई व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, करियर में बदलाव सोच रहा है या किसी रचनात्मक कार्य में कदम रखने वाला है, तो ‘द मैजिशियन’ का आना अत्यंत शुभ माना जाता है।

यह कार्ड यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट है। वह जानता है कि उसे क्या चाहिए और उसे पाने के लिए किस रास्ते पर चलना है। उसकी इच्छाशक्ति मजबूत होती है और वह कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। टैरो के अनुसार, ‘द मैजिशियन’ कार्ड यह संकेत देता है कि व्यक्ति अपने कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक मेहनत करने से पीछे नहीं हटेगा। यही निरंतर प्रयास उसे सफलता तक ले जाएगा।

भाग्य और सफलता की दृष्टि से यह कार्ड इसलिए भी खास है, क्योंकि यह बताता है कि व्यक्ति के प्रयासों को ब्रह्मांड का समर्थन मिल रहा है। टैरो दर्शन में माना जाता है कि जब ‘द मैजिशियन’ आता है, तो व्यक्ति की सोच, वाणी और कर्म एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। यह सामंजस्य ही सफलता की असली कुंजी है। व्यक्ति जो सोचता है, वही बोलता है और वही करता है—और यही एकाग्रता उसे मनचाहा परिणाम दिलाती है।

जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अवसरों के बीच होते हुए भी उन्हें पहचान नहीं पाते। ‘द मैजिशियन’ कार्ड यह याद दिलाता है कि अवसर हमेशा बाहर नहीं होते, बल्कि अक्सर हमारे भीतर ही छिपे होते हैं। हमारी क्षमताएँ, हमारा अनुभव और हमारा आत्मविश्वास ही वे जादुई औजार हैं, जिनसे हम अपने जीवन की तस्वीर बदल सकते हैं। यह कार्ड यह भी सिखाता है कि केवल सपने देखना काफी नहीं, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है।

अंततः, टैरो का ‘द मैजिशियन’ कार्ड यह संदेश देता है कि सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि तैयारी और अवसर के मिलने का परिणाम है। जब यह कार्ड निकलता है, तो समझिए कि जीवन आपको संकेत दे रहा है—अब संदेह छोड़िए, अपनी शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए। क्योंकि इस समय भाग्य आपके साथ है, और आपकी मेहनत उसे सही दिशा देने वाली है। ‘द मैजिशियन’ केवल एक कार्ड नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि आपके हाथों में ही आपके जीवन का जादू है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

पक्षी-पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में गुजरात की एक और उपलब्धि : कच्छ के गौरव में लगे चार

बन्नी का रतन 'छारी-ढंढ' 'रामसर साइट' घोषित : गुजरात का पांचवां और कच्छ का प्रथम अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वेटलैंड बना छारी-ढंढ

(जीएनएस)। गांधीनगर : बन्नी के रतन 'छारी-ढंढ' पक्षी अभयारण्य को आधिकारिक रूप से 'रामसर साइट' घोषित किया गया है, इससे कच्छ के गौरव को चार चांद लग गए हैं। छारी-ढंढ गुजरात का पांचवां और कच्छ का पहला अंतरराष्ट्रीय महत्व वाला वेटलैंड (आर्द्रभूमि) बन गया है। गुजरात के लिए गर्व की बात है कि कच्छ जिले में स्थित छारी ढंढ पक्षी अभयारण्य को अंतरराष्ट्रीय महत्व वाले रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही गुजरात में रामसर स्थलों की संख्या अब बढ़कर पांच हो गई है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने कहा कि छारी-ढंढ पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा मिलने से पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, स्थानीय विकास और वैश्विक पहचान जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आएगा।

श्री मोढवाडिया ने कहा कि गुजरात वेटलैंड के संरक्षण और संवर्धन में सदैव अग्रसर रहा है। देश के कुल वेटलैंड क्षेत्रफल में गुजरात का हिस्सा 21 फीसदी है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। गुजरात के वेटलैंड लगभग 3.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17.8 फीसदी है।

मंत्री श्री मोढवाडिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और वेटलैंड संवर्धन के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य में मरीन नेशनल पार्क (समुद्री राष्ट्रीय उद्यान) और अभयारण्य, खिजड़िया अभयारण्य, नल सरोवर अभयारण्य, छारी ढंढ, कच्छ का छोटा रण-घुड़खर अभयारण्य और पोरबंदर पक्षी अभयारण्य जैसे अनेक वेटलैंड आधारित संरक्षित क्षेत्र हैं। गांधीनगर स्थित गिर फाउंडेशन गुजरात में वेटलैंड इकोसिस्टम की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक शोध, निगरानी कार्यक्रम और वेटलैंड शोध एवं दस्तावेजीकरण में सक्रिय रूप से शामिल है।

▸▸ छारी-ढंढ पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा मिलने से पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, स्थानीय विकास, पर्यटन और वैश्विक पहचान सहित सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा : वन मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया

▸▸ 5 रामसर साइट, 8 राष्ट्रीय वेटलैंड सहित देश के सभी वेटलैंड के कुल क्षेत्रफल में 21 फीसदी हिस्सेदारी के साथ गुजरात देश में सबसे आगे, जो प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आश्रय स्थल के रूप में गुजरात की पहचान को और मजबूत बनाता है : श्री अर्जुन मोढवाडिया

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और वेटलैंड संवर्धन के लिए लगातार प्रयासरत है : श्री अर्जुन मोढवाडिया

उन्होंने कहा कि कच्छ के इको-टूरिज्म और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान माने जाने वाले बन्नी क्षेत्र के छोर पर स्थित 'छारी-ढंढ' कंजर्वेशन रिजर्व को आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वेटलैंड साइट यानी 'रामसर साइट' घोषित किया गया है। नल सरोवर, थोळ, खिजड़िया और वढवाणा के बाद अब 'छारी-ढंढ' गुजरात का पांचवां और कच्छ का पहला रामसर स्थल बन गया है।

श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने कहा कि छारी-ढंढ पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलना गुजरात के लिए गर्व की बात है। इससे राज्य के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। इस मान्यता से छारी-ढंढ वेटलैंड का दीर्घकालिन संरक्षण सुनिश्चित होगा, प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल मजबूत बनेगा और दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, रामसर साइट का दर्जा मिलने से क्षेत्र में इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार और आय के नए अवसर खुलेंगे। पर्यावरण जागरूकता, शैक्षणिक गतिविधियों और समुदाय की सहभागिता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री प्रवीण माली ने कहा कि गुजरात में नल सरोवर, थोळ, खिजड़िया और वढवाणा पक्षी अभयारण्य को पहले ही रामसर साइट की मान्यता मिल चुकी है। अब, छारी-ढंढ पक्षी अभयारण्य के इस सूची में शामिल होने से राज्य की पर्यावरण संरक्षण और वेटलैंड संवर्धन की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो भारत में राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण कुल 115 वेटलैंड में से 8 वेटलैंड गुजरात में हैं। राज्य मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए सभी गुजरातियों को बधाई देते हुए कहा कि इसके अलावा, राज्य में 19 ऐसे वेटलैंड हैं, जो महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, जो प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आश्रय स्थल मुहैया कराते हैं।

उल्लेखनीय है कि आज केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 2 फरवरी, 2026 को 'विश्व वेटलैंड दिवस' से पहले उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के छारी-ढंढ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने से भारत के रामसर नेटवर्क में दो नए वेटलैंड को शामिल करने की घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का रामसर नेटवर्क 2014 में 26 स्थलों से बढ़कर वर्तमान में 98 स्थल हो गया है, जो 276 फीसदी से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। यह अंतरराष्ट्रीय मान्यता पर्यावरण संरक्षण और वेटलैंड संरक्षण के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

नाम की सार्थकता और भौगोलिक महत्व

कच्छी भाषा में 'छारी' का अर्थ क्षार वाली और 'ढंढ' यानी उथला सरोवर। लगभग 227 वर्ग किलोमीटर (22,700 हेक्टेयर) क्षेत्र में फैला यह वेटलैंड रण और घास के मैदान के बीच एक अद्भुत पर्यावास (प्राकृतिक आवास) है। इसे वर्ष 2008 में गुजरात का पहला 'कंजर्वेशन रिजर्व' घोषित किया गया था।

पक्षियों और वन्यजीवों का स्वर्ग

छारी-ढंढ में पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां दर्ज की गई हैं। सर्दियों के दौरान यहां साइबेरिया, मध्य एशिया और यूरोप के 25,000 से 40,000 तक कॉमन क्रेन (कुंज), वेनेलस ग्रेगेरियस (संघी टिटहरी) और डालमेटियन पेलिकन स्थानांतरण करके आते हैं। इसके अतिरिक्त, लेसर फ्लेमिंगो, ग्रेटर फ्लेमिंगो और सारस भी यहां दिखाई देते हैं।

इतना ही नहीं, यहां लुप्तप्राय डालमेशियन पेलिकन, ओरिएंटल डार्टर, ब्लेक-नेक्ड स्टॉर्क और अनेक शिकारी पक्षी भी दिखाई देते हैं। केवल पक्षी ही नहीं, बल्कि यह क्षेत्र चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी (डेजर्ट फॉक्स), स्याहगोश (केरेकल), रेगिस्तानी लोमड़ी और भेड़िये जैसे अनेक वन्यजीवों का भी महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है।

प्रशासन की उपलब्धि

इस अंतरराष्ट्रीय मान्यता को प्राप्त करने में गुजरात के चीफ वाइल्ड लाइफ वॉर्डन डॉ. जयपाल सिंह, गांधीनगर वन्य प्राणी विंग की टीम, मुख्य वन संरक्षक (कच्छ फॉरेस्ट सर्कल, भुज) तथा उप वन संरक्षक कच्छ (पश्चिम) वन विभाग भुज के लगातार प्रयास और कार्य निर्णायक रहे हैं। यह उपलब्धि राज्य एवं केंद्र सरकार (वेटलैंड डिवीजन) के निरंतर मार्गदर्शन में वेटलैंड संरक्षण और इसकी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए किए गए वैज्ञानिक प्रयासों के परिणामस्वरूप हासिल हुई है।

पर्यटन एवं संरक्षण सकारात्मक प्रभाव

रामसर साइट का दर्जा मिलने से छारी-ढंढ को अब वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि मिलेगी, जिससे कच्छ में इको-टूरिज्म का विकास होगा और स्थानीय रोजगार के अवसर के नए द्वार खुलेंगे। इसके साथ ही, इस क्षेत्र के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार फंड और तकनीकी सहायता मिलने का रास्ता भी साफ होगा। वन विभाग कच्छ की इस अमूल्य विरासत को संरक्षित रखने एवं पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।

सप्ताह के दौरान सोना वायदा में 13062 रुपये और चांदी वायदा में 72604 रुपये का ऊछालः क्रूड ऑयल वायदा 592 रुपये तेज

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 23 से 29 जनवरी के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 4391372.37 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 853290.67 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 3537958.21 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 49333 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 50641.76 करोड़ रुपये का हुआ।

आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 724918.03 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 158889 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 180779 रुपये और नीचे में 155248 रुपये पर पहुंचकर, 156341 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 13062 रुपये या 8.35 फीसदी के ऊछाल के साथ 169403 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 14704 रुपये या 10.96 फीसदी की तेजी के संग 148867 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 1926 रुपये या 11.45 फीसदी की मजबूती के साथ 18746 रुपये प्रति 1 ग्राम सप्ताह के अंत में बंद हुआ। सोना-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 158143 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 182130 रुपये और नीचे में 155631 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 14421 रुपये या 9.21 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 170954 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में प्रति 10 ग्राम 162589 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 190018 रुपये और नीचे में 161900 रुपये पर पहुंचकर, 161742 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 22683 रुपये या 14.02 फीसदी की तेजी के संग 184425 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 853290 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 3537958 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 724918 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 49333 पॉइंट के स्तर पर

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 333333 रुपये के भाव पर खूलकर, 420048 रुपये के उच्च और 327502 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 327289 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 72604 रुपये या 22.18 फीसदी के ऊछाल के साथ 399893 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 78311 रुपये या 23.56 फीसदी बढ़कर 410704 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 78583 रुपये या 23.64 फीसदी की तेजी के संग सप्ताह के अंत में 411059 रुपये प्रति किलो हुआ।

मेटल वर्ग में 69299.43 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 108.2 रुपये या 8.3 फीसदी ते ज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1411.5 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 23.9 रुपये या 7.54 फीसदी तेज होकर सप्ताह के अंत में यह कॉन्ट्रैक्ट 340.75 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 23.35 रुपये या 7.34 फीसदी बढ़कर 341.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि सीसा फरवरी वायदा 10.1 रुपये या 5.27 फीसदी की बढ़त के साथ सप्ताह के अंत में 201.65 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 59025.54 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 5495 रुपये के भाव पर खूलकर, 6135 रुपये के उच्च और 5475 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 592 रुपये या 10.88 फीसदी की मजबूती के साथ 6032 रुपये प्रति बैरल बंद हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 589 रुपये या 10.82 फीसदी की तेजी के संग सप्ताह के अंत में 6031 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 328 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 363.3 रुपये के उच्च और 313.8 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 326.4 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 25.6 रुपये या 7.84 फीसदी की मजबूती के साथ 352 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 25.8 रुपये या 7.92 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 351.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर बंद हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 976 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 13.1 रुपये या 1.34 फीसदी की तेजी के संग 992.1 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 432316.08 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 292601.96 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 58128.77 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 5211.94 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 661.69 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 5149.27 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 9549.62 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 49399.82 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 44.41 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 4226 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 30090 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 19027 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 254253 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 32630 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8798 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 18826 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 40699 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 18277 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 16680 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 43500 पॉइंट पर खूलकर, 52600 के उच्च और 43300 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 6344 पॉइंट बढ़कर 49333 पॉइंट के स्तर पर

15 अप्रैल तक साबरमती रेलवे स्टेशन पर नए प्रवेश एवं निकास द्वार की व्यवस्था

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मण्डल के साबरमती स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। साबरमती बीजी (धरमनगर साइड) नई स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है जबकि अन्य पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है।

यात्रियों की सुविधा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से 15 अप्रैल 2026 तक आगमन एवं प्रस्थान हेतु नए प्रवेश एवं निकास द्वार तथा पिक-अप एवं ड्रॉप की व्यवस्था की गई है। विवरण इस प्रकार हैः

1. प्रस्थान करने वाले यात्रियों हेतु प्रवेश एवं निकास व्यवस्था

▸▸ प्रवेश द्वार (Entry Gate): यात्रियों के वाहनों का प्रवेश MMTS बिल्डिंग (बुलेट ट्रेन स्टेशन) के पास से किया जा रहा है। (डायग्राम में दी गई ग्रीन लाइन के अनुसार)

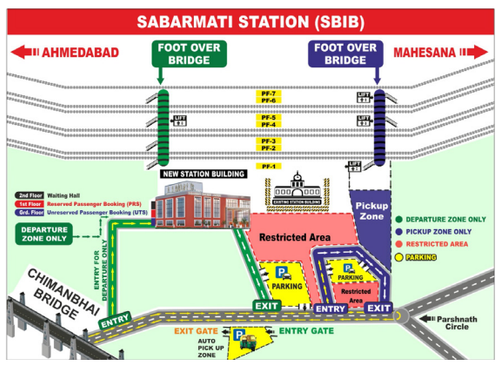

▸▸ यात्री नवनिर्मित स्टेशन बिल्डिंग में प्रवेश कर लिफ्ट, एस्कलेटर एवं सीढ़ियों के माध्यम से सेकंड फ्लोर से होते हुए सभी प्लेटफार्मों पर जा सकते है।

▸▸ यात्रियों को ड्रॉप करने वाले वाहन पुराने प्रवेश द्वार से बाहर निकल सकते है।

2. आगमन करने वाले यात्रियों हेतु निकास एवं पिक-अप व्यवस्था

▸▸ निकास द्वार (Exit Gate): महेसाणा साइड फुट ओवर ब्रिज के पास से निकास की व्यवस्था की गई है। (डायग्राम में दी गई पर्पल लाइन के अनुसार)

▸▸ इसी स्थान पर यात्रियों के लिए पिक-अप जोन भी बनाया गया है।

3. पार्किंग सुविधा

▸▸ यात्रियों की सुविधा के लिए निकास द्वार के निकट दो स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

4. प्लेटफार्म कनेक्टिविटी

▸▸ सभी प्लेटफार्म (PF-1 से PF-7) दोनों फुट ओवर ब्रिज से कनेक्टटेड हैं। (वर्तमान में PF-2 और PF-3 से ट्रेन संचालन पुनर्निर्माण कार्य के कारण बंद है)

5. नवनिर्मित स्टेशन बिल्डिंग में यात्री सुविधाएं

▸▸ भूतल (Ground Floor): अनारक्षित टिकट बुकिंग (UTS)

▸▸ प्रथम तल (First Floor): आरक्षित टिकट बुकिंग (PRS)

▸▸ द्वितीय तल (Second Floor): प्रतीक्षालय

सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे नई यातायात व्यवस्था, संकेतकों तथा रेलवे एवं आरपीएफ एवं रेलकर्मियों के निर्देशों का पालन करें।

भावनगर-ओखा एक्सप्रेस और भावनगर-साबरमती इंटरसिटी ट्रेन में अतिरिक्त कोच की सुविधा

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर रेल प्रशासन ने भावनगर-ओखा-भावनगर एक्सप्रेस ट्रेन (19209/19210) में अस्थायी तौर पर एक थर्ड एसी कोच तथा भावनगर-साबरमती-भावनगर इंटरसिटी ट्रेन (20966/20965) में अस्थाई रूप से 4 अतिरिक्त जनरल कोच की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार अतिरिक्त कोच का विवरण निम्नानुसार हैः-

1.ट्रेन नंबर 19209/19210 भावनगर-ओखा-भावनगर एक्सप्रेस ट्रेन में एक थर्ड एसी कोच 01.02.2026 से 05.02.2026 तक लगाया जाएगा।

2.ट्रेन नंबर 20966/20965 भावनगर-साबरमती-भावनगर इंटरसिटी में 04 जनरल कोच 01.02.2026 से 05.02.2026 तक लगाया जाएगा।

इस ट्रेन के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

ग्रीनफील्ड में भारत का शक्ति प्रदर्शन न्यूजीलैंड पर 46 रन की जीत के साथ टी20 सीरीज 4-1 से अपने नाम

(जीएनएस)। तिरुवनंतपुरम। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अपनी आखिरी द्विपक्षीय श्रृंखला में भारतीय टीम ने दमदार संदेश दे दिया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पांचवें और अंतिम टी20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 46 रनों से हराकर न सिर्फ मैच जीता, बल्कि पांच मैचों की सीरीज भी 4-1 से अपने नाम कर ली। यह जीत भारतीय टीम की आक्रामक बल्लेबाजी, संतुलित गेंदबाजी और मजबूत टीम संयोजन का बेहतरीन उदाहरण रही। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कप्तान सूर्यकुमार यादव ने किया। हालांकि शुरुआत भारत के लिए कुछ खास नहीं रही। संजू सैमसन केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अभिषेक शर्मा ने 30 रनों की तेज पारी खेलने के बाद अपना विकेट गंवा दिया। महज 42 रन पर दो विकेट गिरने से ऐसा लगा कि भारतीय पारी थोड़ी लड़खड़ा सकती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मैच की दिशा ही बदल दी।

ईशान किशन ने मैदान पर आते ही आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं किया और सिर्फ 43 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उनकी इस विस्फोटक पारी में 10 शानदार छक्के और 6 चौके शामिल रहे। दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी अपने चिरपरिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों में 63 रन ठोके। दोनों के बीच हुई 137 रनों की साझेदारी ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की कमर तोड़ दी। महज 57 गेंदों में यह साझेदारी पूरी हुई और स्टेडियम में मौजूद दर्शक भारतीय बल्लेबाजी के इस तूफान के गवाह बने।

पारी के अंतिम ओवरों में हार्दिक पंड्या ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने 17 गेंदों में 42 रन बनाकर स्कोर को और ऊंचाई तक पहुंचा दिया। भारत ने अंतिम 10 ओवरों में 169 रन जोड़ते हुए 5 विकेट पर 271 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया,

जो टी20 क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य माना जाता है।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने भी हार मानने के मूड में शुरुआत नहीं की। फिन एलन ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया और 38 गेंदों में 80 रन बनाए। रचिन रवींद्र ने भी उनका अच्छा साथ निभाते हुए सिर्फ 17 गेंदों में 30 रन जड़ दिए। दूसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी हुई और एक समय ऐसा लगा कि मुकाबला रोमांचक हो सकता है। लेकिन यहीं से भारतीय गेंदबाजों ने मैच पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया। अर्शदीप सिंह ने अपनी सटीक लाइन-लेंथ और स्विंग से न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। उन्होंने पांच विकेट झटककर कीवी बल्लेबाजों को एक के बाद एक पवेलियन भेजा। अक्षर पटेल ने भी शानदार सहयोग देते हुए तीन अहम विकेट अपने नाम किए, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने एक विकेट लिया। लगातार गिरते विकेटों के दबाव में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19.4 ओवर में 225 रन पर ऑलआउट हो गई।

इस तरह भारत ने 46 रनों से मुकाबला जीत लिया और सीरीज का अंत शानदार अंदाज में किया। भारत पहले ही शुरुआती तीन मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा चुका था। चौथे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने वापसी जरूर की थी, लेकिन निर्णायक मैच में भारतीय टीम ने किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दिखाई।

बिना अदालती आदेश जेल से बाहर आया गैंगस्टर, बांदा कारागार में मचा प्रशासनिक भूचाल

(जीएनएस)। बांदा। उत्तर प्रदेश की जेल व्यवस्था में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने प्रशासन, पुलिस और न्यायिक तंत्र तीनों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। जिला कारागार बांदा से कुख्यात गैंगस्टर और स्क्रैप माफिया रवि काना की कथित तौर पर बिना किसी स्पष्ट न्यायिक आदेश के रिहाई ने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सामने आते ही कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं हरकत में आ गया और प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही मानते हुए बांदा जेल के जेलर विक्रम सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है।

रविंद्र उर्फ रवि नागर उर्फ रवि काना गौतमबुद्ध नगर के थाना सेक्टर-63 में दर्ज एक आपराधिक मामले में वांछित था। वह पहले से ही एक अन्य मुकदमे में बांदा जिला कारागार में निरुद्ध था। इसी बीच नोएडा पुलिस ने 28 जनवरी को उसके खिलाफ बी-वारंट जारी कराया, जिसके तहत 29 जनवरी को उसे अदालत में पेश किया गया। आमतौर पर बी-वारंट पर पेश किए गए किसी आरोपी को बिना स्पष्ट रिहाई आदेश के जेल से बाहर नहीं छोड़ा जाता, लेकिन इस मामले में जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया।

अदालती रिकॉर्ड के अनुसार 29 जनवरी को पेशी के बाद शाम 6 बजकर 39 मिनट पर आरोपी को जेल से रिहा कर दिया गया, जबकि संबंधित मुकदमे में न्यायिक कार्यवाही अभी जारी थी और किसी भी दस्तावेज में उसकी रिहाई का स्पष्ट आदेश दर्ज नहीं था। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी गंभीर चूक कैसे हुई और किस स्तर पर लापरवाही बरती गई।

गौतमबुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीर मानते हुए जेल प्रशासन से जवाब तलब किया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से

पूछा है कि बी-वारंट पर तलब आरोपी को किन परिस्थितियों में रिहा किया गया और यदि यह रिहाई अवैध थी, तो इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों न कराई जाए। अदालत की टिप्पणी ने इस प्रकरण को और संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि इसमें न सिर्फ प्रशासनिक गलती, बल्कि संभावित आपराधिक लापरवाही की आशंका भी जताई गई है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जेल प्रशासन को यह भली-भांति जानकारी थी कि आरोपी को नोएडा के मामले में बी-वारंट पर अदालत में पेश किया गया है। इसके बावजूद यदि उसे रिहा कर दिया गया, तो यह सामान्य भूल नहीं, बल्कि गंभीर प्रशासनिक चूक मानी जाएगी। अदालत का यह रुख साफ संकेत देता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कानूनी शिकंजा और कस सकता है। वहीं, जेल प्रशासन ने अपने बचाव में अलग तर्क पेश किया है। जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम का कहना है कि रवि काना के खिलाफ दर्ज 20 से अधिक मामलों में पहले ही रिहाई आदेश प्राप्त हो चुके थे। उनके अनुसार अंतिम रिहाई आदेश 28 जनवरी की सुबह जारी हुआ था। 29 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई गई, लेकिन शाम तक कोई नया कस्टडी वारंट या लिखित निर्देश जेल को प्राप्त नहीं हुआ। जेल अधीक्षक का दावा है कि वैध निरुद्ध आदेश के अभाव में नियमों के तहत आरोपी को रिहा किया गया। उनका यह भी कहना है कि संबंधित कस्टडी वारंट बाद में रात करीब 7 बजकर 45 मिनट पर जेल की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर प्राप्त हुआ, जब आरोपी को छोड़ा जा चुका था। हालांकि, प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर इस दलील को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब आरोपी को बी-वारंट पर पेश किया गया था, तो उसकी रिहाई से पहले संबंधित अदालत या पुलिस से स्पष्ट स्थिति क्यों नहीं पूछी गई। इसी बिंदु को लेकर जेलर विक्रम सिंह यादव की भूमिका संदेह के घेरे में आई और उन्हें निलंबित कर दिया गया।

इस पूरे मामले ने उत्तर प्रदेश की जेल व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। एक कुख्यात गैंगस्टर, जिसके खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले हैं, यदि बिना स्पष्ट आदेश जेल से बाहर आ सकता है, तो यह कानून-व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक संकेत है। अब निगाहें न्यायिक जांच पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि यह महज लापरवाही थी या इसके पीछे कोई और वजह भी छिपी हुई है। आने वाले दिनों में इस मामले में एफआईआर, विभागीय कार्रवाई और अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

देश की नवीकरणीय ऊर्जा में 16.50 प्रतिशत योगदान के साथ गुजरात देश में अग्रसर

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है और परंपरागत ईंधन पर निर्भरता में कमी लाने के लिए महत्वपूर्ण पहलें की हैं। इस व्यापक आयोजन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत की 50 प्रतिशत बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा में नए मानदंड स्थापित किए हैं, जो इस राष्ट्रीय लक्ष्य में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। दिसंबर-2025 तक के आँकड़े दर्शाते हैं कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में गुजरात का योगदान सर्वाधिक है। राज्य की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 42.583 गीगावाट तक पहुँची है, जो भारत की कुल क्षमता में 16.50 प्रतिशत का योगदान दर्शाती है। इसके अतिरिक्त; गुजरात कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (42.583 गीगावाट) में प्रथम स्थान पर है तथा स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता (14,820.94 मेगावाट) में भी प्रथम स्थान पर है और सौर ऊर्जा क्षमता (25,529.40 मेगावाट) में दूसरे स्थान पर है। सोलर रूफटॉप इन्स्टॉलेशन में गुजरात देश में प्रथम स्थान पर है, जिसमें 11 लाख सोलर रूफटॉप सिस्टम्स के माध्यम से 6,412.80 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन हो रहा है।

सौर ऊर्जा में गुजरात अग्रसर

दिसंबर-2025 तक 25,529.40 मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ सौर ऊर्जा क्षेत्र में गुजरात अग्रसर रहा है। इसमें ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स से 17,771.21 मेगावाट, सोलर रूफटॉप सिस्टम्स से 6,412.80 मेगावाट (जिसमें सूर्य गुजरात द्वारा 2,073.65 मेगावाट, पीएम सूर्य घर योजना द्वारा 1,913 मेगावाट तथा अन्य 2,267.04 मेगावाट), हाइब्रिड परियोजनाओं से 1,172.38 मेगावाट तथा ऑफ-ग्रिड सिस्टम्स (पीएम कुसुम सहित) से 173.01 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। गुजरात में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए चारणका (749 मेगावाट), राधानेसडा (700 मेगावाट) और धोलेरा (300 मेगावाट) में सोलर पार्क कार्यरत हैं। 37.35 गीगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ कच्छ के खावडा में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित हो रहा है, जिसमें हाल में 11.33 गीगावाट उत्पादन प्राप्त करने में सफलता मिली है। गुजरात ने 11 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम्स स्थापित करने की उपलब्धि भी हासिल की है; जो आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में 6,412.80 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। गुजरात ने वर्ष 2016 से घरों में छत पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया है और पीएम सूर्य घर योजना के लॉन्च होने तक उसे समर्थन मिला है। इसके कारण भारत के कुल रूफटॉप सोलर इन्स्टॉलेशन में राज्य का योगदान 25 प्रतिशत से अधिक हुआ है। कृषि क्षेत्र में पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत 12,700 स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड सोलर वॉटर पंप स्थापित किए गए हैं, जिनके द्वारा 89.54 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन हो रहा है।

14,820.94 मेगावाट उत्पादन के साथ पवन ऊर्जा में गुजरात अग्रसर

भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र में गुजरात ने प्रथम पवन ऊर्जा नीति लागू करके महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिसंबर-2025 तक पवन ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की स्थापित क्षमता 14,820.64 मेगावाट है, जिसमें कच्छ का योगदान सर्वाधिक 7,476.73 मेगावाट है। जामनगर (1,867.65 मेगावाट), देवभूमि द्वारका (1,281.26 मेगावाट), अमरेली (973.85 मेगावाट), राजकोट (874.90 मेगावाट), भावनगर (618.80 मेगावाट), मोरबी (568.6 मेगावाट), सुरेन्द्रनगर (456.6 मेगावाट) तथा पाटण (208.2 मेगावाट) जिलों में भी पवन ऊर्जा की उल्लेखनीय स्थापित क्षमता है। राज्य ने 2018 में हाइब्रिड पॉलिसी तथा रिन्यूएबल एनर्जी (आरई) पॉलिसी 2023 अंतर्गत पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं द्वारा 2,398.77 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ी है। 80 प्रतिशत से अधिक टर्बाइन सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर कार्यरत हैं, जहाँ सुदृढ़ ढाँचागत सुविधाएँ तथा अनुकूल प्रणालियाँ विकसित की गई हैं। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कारण अनुमानित 2.37 लाख प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगार का सृजन हुआ है। परियोजनाओं के तेज क्रियान्वयन एवं ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा सेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुव्यवस्थित तथा पारदर्शी प्रणाली विकसित की है। नेट मीटरिंग नियमों के तहत राज्य ने 6.40 जीडब्लूपी से अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित की है, जो इसे इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाती है।

▸▸ राज्य की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 42.583 गीगावाट, जिसमें 14,820.94 मेगावाट पवन ऊर्जा तथा 25,529.40 मेगावाट सौर ऊर्जा शामिल

▸▸ रूफटॉप सोलर में गुजरात शीर्ष पर, 11 लाख से अधिक इन्स्टॉलेशन द्वारा 6,412.80 मेगावाट बिजली का उत्पादन

▸▸ गुजरात में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हुए विकास से अनुमानित 2.37 लाख प्रत्यक्ष तथा परोक्ष नौकरियों का सृजन

भविष्य के लिए गुजरात सज्ज : 2030 तक 105 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य

गुजरात अपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का निरंतर विस्तार कर रहा है और हाल में 5,203 परियोजनाएँ चल रही हैं। इन परियोजनाओं में 4,992 सौर ऊर्जा परियोजनाएँ (32.22 गीगावाट), 72 पवन ऊर्जा परियोजनाएँ (15 गीगावाट) तथा 139 हाइब्रिड एनर्जी परियोजनाएँ (21.15 गीगावाट) शामिल हैं। इनसे 68.37 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त होगी। गांधीनगर में आयोजित आरई इन्वेस्ट 2024 कार्यक्रम में राज्य ने वर्ष 2030 तक 105 गीगावाट उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो भारत के 500 गीगावाट अजीवाश्म ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य में 20 प्रतिशत योगदान देगा।

गुजरात की मजबूत नीतियों से ऊर्जा क्षेत्र का विकास

1993 में प्रथम पवन ऊर्जा नीति लागू करने के बाद गुजरात सरकार ने समय-समय पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण नीतियाँ लागू की हैं; जिनमें सौर ऊर्जा नीतियाँ (2009, 2015, 2021), वेस्ट टू एनर्जी एंड स्मॉल हाइडल पॉलिसी (2016) और विंड-सोलर हाइब्रिड पॉलिसी (2018) शामिल हैं। 2022 में अपडेटेड वेस्ट टू एनर्जी नीति तथा गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी-2023 द्वारा सोलर, विंड, हाइब्रिड तथा वितरण आधारित प्रोजेक्ट्स के लिए एकीकृत ढाँचा मुहैया कराया गया है। इस नीति के अंतर्गत क्षमता सीमा समाप्त की गई है तथा टैरिफ, ग्रिड चार्ज, ऊर्जा लेखा, क्रॉस सब्सिडी एवं बैंकिंग चार्ज के बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त; गुजरात डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी बाइलेटरल प्रोक्योरमेंट (डीआरईबीपी) योजना क्लीन एनर्जी में अग्रणी राज्य के रूप में गुजरात की स्थिति को मजबूत बनाती है। तो 2025 की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी विशाल क्षमता तथा वितरित नवीकरणीय ऊर्जा को तेज गति देने पर केन्द्रित है। इसमें ऑन-डिमांड कनेक्टिविटी, फ्लेक्सिबल कमीशनिंग समयसीमा, पुराने विंड प्रोजेक्ट्स की रीपावरिंग तथा सोलर, पवन एवं हाइब्रिड सिस्टम्स के साथ बैटरी स्टोरेज का आसान समन्वय सुनिश्चित किया गया है। यह नीति उभरती नवीकरणीय ऊर्जा टेक्नोलॉजीस, निजी क्षेत्र की भागीदारी, आरई मैन्युफैक्चरिंग व रिसाइक्लिंग तथा अक्षय-ऊर्जा-सेतु पोर्टल द्वारा डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से नवीनता को प्रोत्साहन देती है।

वर्ष 2026 के पहले ही महीने में राज्य को 4870 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों की भेंट मिली

▸▸ जिन कार्यों का शिलान्यास होता है, उनका लोकार्पण उसी सरकार के कार्यकाल में हो; ऐसी समयबद्ध योजना की कार्य संस्कृति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित की है, जिसे गुजरात ने साकार किया है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ मुख्यमंत्री ने सूरतवासियों को 342 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी

▸▸ सूरत महानगर पालिका के 173.78 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 169 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास

▸▸ सूरत विकास, स्वच्छता और शहरीकरण का मॉडल शहर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ तापी शुद्धिकरण परियोजना के परिणामस्वरूप उकाई से लेकर सूरत तक 85 किमी दूर से आने वाला औद्योगिक गंदा पानी अब तापी नदी में मिलने से रुक गया है : केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल

▸▸ गोटालावाडी टेनामेंट के 1304 आवासों का जन भागीदारी से पुनर्विकास पूर्ण, मुख्यमंत्री के करकमलों से लोकार्पण और लाभार्थियों के लिए कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ आयोजित हुआ

▸▸ 70 करोड़ रुपए की लागत से डभोली में नव निर्मित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम का लोकार्पण

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य के लोगों की 'ईज ऑफ लिविंग' बढ़ाने के लिए वर्ष 2026 के पहले ही महीने में पूरे राज्य में 4870 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्य सरकार ने भेंट दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को सूरत महानगर पालिका के 173.78 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 169 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास कर सूरतवासियों को कुल 342 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भेंट दी। उन्होंने इस अवसर पर स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार द्वारा जिन कार्यों का शिलान्यास किया जाता है, उन कार्यों का लोकार्पण भी उसी सरकार के कार्यकाल में सुनिश्चित हो; ऐसी समयबद्ध योजना और कार्य संस्कृति विकसित की है। उसी कार्य संस्कृति को हमने गुजरात में साकार किया है। राज्य सरकार की 'सार्वजनिक आवास पुनर्विकास योजना-2016' अंतर्गत कतारगाम क्षेत्र के गोटालावाडी टेनामेंट के 1304 आवासों का पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर पुनर्विकास पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल की विशेष उपस्थिति में इन आवासों का लोकार्पण किया तथा लाभार्थियों के लिए कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ भी आयोजित किया। मुख्यमंत्री ने सूरत के अक्षरवाडी, डभोली और कतारगाम स्थित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में कहा कि सूरत आज देशभर में विकास, स्वच्छता और शहरीकरण का उत्कृष्ट मॉडल बन चुका है। सूरत की स्वच्छता सूरतवासियों में आए सकारात्मक बदलाव और स्वच्छता प्रेम का परिणाम है। अपनी स्वच्छता, अनुशासन और आधुनिक शहरी योजना के बल पर सूरत आज मुंबई जैसे महानगरों को भी पीछे छोड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने सूरत को राज्य के विकास का 'ग्रोथ इंजन' बने हुए सूरत के विकास को उदाहरणीय बताते हुए कहा कि सूरत देश का सबसे तेजी से विकसित हो रहा शहर है। औद्योगिक विकास के कारण समूचे भारत से लोग यहां रोजगार के लिए आकर बस रहे हैं, इसी कारण सूरत को 'मिनी भारत' की उपाधि मिली है। डायमंड और टेक्सटाइल कैपिटल के रूप में पहचाना जाने वाला सूरत आज स्वच्छता, ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र से 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का विजन साकार हो रहा है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण और हमारा संकल्प हम सभी के सहयोग से ही पूरा होगा।

उन्होंने कहा कि सूरत जैसे शहर देश की आर्थिक गतिशीलता के केंद्र हैं और 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' की यात्रा में नेतृत्व प्रदान करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सूरत को मिले 342 करोड़ रुपए के विकास कार्य शहरी नागरिकों की 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ाएंगे। गोटालावाडी टेनामेंट के 1304 आवासों के पुनर्विकास से लाभार्थी परिवारों को सुरक्षित, आधुनिक और आरामदायक आवास मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, ई मोबिलिटी, प्रदूषण मुक्त परिवहन और सार्वजनिक आवास योजनाओं में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य सरकार द्वारा 2005 में शुरू की गई शहरी विकास यात्रा के परिणामस्वरूप आज गुजरात सर्वांगीण विकास का मॉडल स्टेट बना है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि शहर के प्रत्येक क्षेत्र का समान विकास हो; इसके लिए सरकार और स्थानीय तंत्र लगातार प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने कहा कि कतारगाम, वराछा और मोटा वराछा क्षेत्रों में जन सुविधाओं का विस्तार हुआ है। राज्य की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक लाइब्रेरी 70 करोड़ रुपए की लागत से कतारगाम में तैयार की जा रही है, जिसका लोकार्पण आगामी तीन महीनों में होगा। यह लाइब्रेरी हजारों युवाओं का उज्ज्वल भविष्य गढ़ेगी।

उन्होंने आगे कहा कि डभोली क्षेत्र में निर्मित नया ऑडिटोरियम कतारगाम, वराछा और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं, कला-प्रेमियों और नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा। नानपुरा गांधी स्मृति, सरदार स्मृति-वराछा और संजीव कुमार ऑडिटोरियम-पाल के बाद अब कतारगाम में भी आधुनिक ऑडिटोरियम बनने से सूरत शहर में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरत महानगर पालिका सौर ऊर्जा के उपयोग से प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ रुपए की बचत कर रही है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक उदाहरणात्मक कदम है। श्री संघवी ने कहा कि सरकार द्वारा निर्मित ऑडिटोरियम, ब्रिज, लाइब्रेरी और स्कूल जैसे परियोजना केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए हैं। इनकी सुरक्षा, देखभाल और स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

उन्होंने कहा कि गोटालावाडी टेनामेंट के पुनर्विकास से 1304 परिवारों के जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा और शुभकामनाएं दी कि परिवार जब अद्भुत खुशी के साथ अपने नए घरों में प्रवेश करेंगे, तो उनके सपने साकार होंगे।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि जिस गति से सूरत का विकास हो रहा है, वह अन्य शहरों के लिए उदाहरण है। एक समय अस्वच्छ रहा सूरत आज देश का नंबर-वन स्वच्छ शहर बन चुका है। अगले 50 वर्षों की जनसंख्या को ध्यान में रखकर पानी की व्यवस्था का समुचित नियोजन किया गया है। देश में 123 से अधिक ब्रिज के साथ सूरत महानगर पालिका नंबर वन बनी है। सरकार और पालिका के अधिकारियों-पदाधिकारियों के संयुक्त प्रयासों से विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सूरत महानगर पालिका प्रतिवर्ष गंदे पानी का ट्रीटमेंट कर 400 करोड़ रुपए की आय अर्जित कर रही है, जो भविष्य में बढ़कर 700 करोड़ रुपए हो जाएगी। वेस्ट वॉटर से इतनी बड़ी आय प्राप्त करने वाली सूरत देश की पहली महानगर पालिका है।

श्री पाटिल ने आगे कहा कि तापी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 931 करोड़ रुपए की तापी शुद्धिकरण परियोजना के चलते उकाई से लेकर सूरत तक 85 किमी दूर से आने वाला औद्योगिक गंदा पानी अब तापी नदी में मिलना बंद हो गया है। उल्लेखनीय है कि 70 करोड़ रुपए की लागत से डभोली में नव निर्मित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम, 12.66 करोड़ रुपए की लागत से जियाव बुडिया लेक गार्डन का लोकार्पण तथा सूरत मनपा द्वारा बनासकांठा जिले के डीसा तहसील के विठोदर गांव में स्थापित 55.56 करोड़ रुपए की लागत से 10 मेगावाट क्षमता का ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, लेक गार्डन रीडिंग रूम, अर्बन हेल्थ सेंटर, शेल्टर होम सहित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण तथा ड्रेनेज, हाइड्रोलिक आदि विभागों के कार्यों का शिलान्यास किया गया।

महापौर श्री दक्षेशभाई मावाणी ने कहा कि सूरत शहर की सांस्कृतिक विरासत को निरंतर बनाए रखने के उद्देश्य से लोकार्पित आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह ऑडिटोरियम कतरगामवासियों के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट के तहत सूरत महानगर पालिका अपनी आवश्यकता की 28.5 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाली महानगर पालिका बन गई है, जिससे प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपए की बचत होगी। सूरत महानगर पालिका मूल बिजली बिल में 70 करोड़ रुपए की बचत करने वाली महानगर पालिका बनी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सूरत वर्ष 2030 तक सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने वाली देश की नंबर वन महानगर पालिका बनेगी। साथ ही, गोटालावाडी में 1304 टेनामेंट के साथ किए गए रिडेवलपमेंट कार्य से निवासियों का अपने पक्के घर का सपना साकार हुआ है। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई, सांसद श्री मुकेशभाई दलाल, विधायकगण सर्वश्री पूर्णेशभाई मोदी, विनोदभाई मोरडिया, प्रवीणभाई घोघरी, मनुभाई पटेल, किशोर कानाणी (कुमार), श्रीमती संगीता बेन पाटील, अरविंद राणा, मुकेशभाई पटेल, कांतिभाई बलर, संदीप देसाई, उप महापौर डॉ. नरेंद्र पाटील, स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री राजन पटेल, महानगर पालिका आयुक्त एन. नागराजन, शहर संगठन प्रमुख परेश पटेल सहित कॉर्पोरेटर, महानगर पालिका की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष, पदाधिकारी-अधिकारी एवं बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ डायमंड और टेक्सटाइल कैपिटल के रूप में पहचाना जाने वाला सूरत, स्वच्छता, ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी अग्रसर

▸▸ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू की गई शहरी विकास यात्रा के परिणामस्वरूप आज गुजरात सर्वांगीण विकास का मॉडल स्टेट बना है

.....

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▸▸ शहर के हर क्षेत्र का समान विकास हो; इसके लिए सरकार और स्थानीय तंत्र का निरंतर प्रयास होता है

▸▸ नई परियोजना और विकास परियोजनाएं केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए बनती हैं; इन संपत्तियों की देखभाल करना हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है

रेलवे के "मेरी टिकट, मेरी शान" अभियान में भाग लेकर स्नेहा फाउन्डेशन ने जागरूकता फैलाने में किया सहयोग

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा रेल यात्रियों में वैध टिकट लेकर यात्रा करने एवं डिजिटल रेलवे सेवाओं के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे "मेरी टिकट, मेरी शान - विकसित भारत के लिए मेरा योगदान" अभियान के अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी 2026 (शनिवार) को भावनगर टर्मिनस, जूनागढ़ एवं वेरावल रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल माध्यमों के जरिए जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गईं। अभियान के दौरान स्टेशनों पर डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से आकर्षक क्रिएटिव्स प्रदर्शित किए गए, जिनके माध्यम से यात्रियों को टिकट लेकर यात्रा करने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर वाणिज्य विभाग के रेलवे कर्मचारियों (टिकट निरीक्षकों) ने

यात्रियों से सक्रिय संवाद स्थापित किया तथा उन्हें रेलवन (RailOne) ऐप की विस्तृत जानकारी दी। यात्रियों को ऐप के प्रमुख लाभों जैसे आसान टिकट बुकिंग, ट्रेनों की रीयल-टाइम जानकारी एवं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न रेलवे सेवाओं के उपयोग के बारे में अवगत कराया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह पहल यात्रियों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने, डिजिटल रेलवे सेवाओं को अपनाने तथा एक अधिक सुरक्षित, पारदर्शी एवं कुशल रेलवे प्रणाली के निर्माण में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करती है। इसी क्रम में भावनगर टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर वाणिज्य विभाग द्वारा "मेरी टिकट – मेरी शान, विकसित भारत के लिए मेरा योगदान" अभियान के अंतर्गत विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्नेहा फाउंडेशन के आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर एवं समाज के हाशिए पर खड़े वंचित बच्चों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने जागरूकता नारे लगाकर यात्रियों से टिकट लेकर ही यात्रा करने की अपील की। इस अभियान के माध्यम से जहां यात्रियों में रेलवे नियमों के प्रति जागरूकता फैली, वहीं स्नेहा फाउंडेशन के बच्चों को भी रेलवे नियमों, नागरिक जिम्मेदारियों एवं ईमानदार यात्रा के महत्व की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई।

यह कार्यक्रम बच्चों के लिए एक प्रेरणादायी अनुभव सिद्ध हुआ, जिससे उनमें आत्मविश्वास के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का भी विकास हुआ। बच्चों को इस जन-जागरूकता अभियान का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान कर समाज के प्रति उनकी सकारात्मक भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।

माननीय केन्द्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना द्वारा इंदौर स्टेशन का निरीक्षण एवं रीडेवलपमेंट कार्यों की समीक्षा

रतलाम। माननीय केन्द्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने 31 जनवरी 2026 को इंदौर प्रवास के दौरान इंदौर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा की तथा रतलाम मंडल द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों एवं यात्री सुविधा से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से करने हेतु निर्देशित किया। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कंस्ट्रक्शन कार्यालय में आयोजित बैठक में इंदौर स्टेशन रीडेवलपमेंट सहित क्षेत्र में चल रहे विभिन्न रेलवे विकास एवं निर्माण कार्यों पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में स्टेशन रीडेवलपमेंट की प्रगति, यात्री सुविधाओं के विस्तार, संरचनात्मक कार्यों, समयबद्ध निष्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

"इस अवसर पर माननीय सांसद इंदौर श्री शंकर लालवानी द्वारा माननीय मंत्री

जी को इंदौर क्षेत्र में रेलवे के अंतर्गत संचालित प्रमुख विकास एवं निर्माण परियोजनाओं के संबंध में अवगत कराया गया। इसमें इंदौर–दाहोद नई रेल लाइन, इंदौर–खंडवा रेल खंड का आमान परिवर्तन, इंदौर-मनमाड नई रेल लाइन, इंदौर - बुधनी नई रेल लाइन सहित अन्य प्रगतिरत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ लगभग 75 वर्ष पुराने शास्त्री ब्रिज के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव पर चर्चा की गई तथा क्षेत्र की भविष्य की आवश्यकताओं पर भी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।"

माननीय श्री सोमन्ना ने इंदौर स्टेशन रीडेवलपमेंट एवं अन्य विकास कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं, जिससे यात्रियों को बेहतर एवं आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकें।

इस दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक(इंफ्रा) श्री अक्षय कुमार एवं मुख्य इंजीनियर(निर्माण), सहित रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।